

प्रेषक,

टीकम सिंह पवार
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई विभाग

देहरादून, दिनांक 03-09-2007

विषय: जनपद देहरादून में बीजापुर कैनाल के अपस्ट्रीम में गुच्युपानी नामक स्थान पर पेयजल योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2859/मुअवि/बजट/बी-1 योजना दि० 15.06.07 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "जनपद देहरादून में बीजापुर कैनाल के अपस्ट्रीम में गुच्युपानी नामक स्थान पर पेयजल योजना का सर्वेक्षण कार्य की योजना" लागत रु० 60.64 लाख टी०ए०सी० के परीक्षणोपरान्त सार्वतुत लागत रु० 45.85 लाख (रुपये पैंतालीस लाख पचासी हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा योजना के क्रियान्वयन हेतु रु० 10.00 लाख (रुपये दस लाख मात्र) की धनराशि को व्यय करने स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :-

- 1- उक्त योजना का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व इन योजना के आगणन पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
- 2- उक्त कार्यो के निष्पादन में वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्वेज रूल्स, टेण्डर विषयक नियम, मितव्ययता के सम्बन्ध में आदेश एवं शासन द्वारा इस विषय में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का पालन किया जाय।
- 3- स्वीकृत की जा रही योजनाओं का कार्य दिनांक-31.03.08 तक पूर्ण किया जाय और पूर्ण करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखाकार एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त विवरण पत्र उपलब्ध कराने व पूर्व स्वीकृत धनराशि के पूर्ण उपभोग के बाद ही अगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।
- 4- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 5- आगणनों में उल्लिखित दरों का दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित कराया जाय। जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बजार भाव से ली गयी है, की स्वीकृति भी नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से प्राप्त की जाय।
- 6- कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायेगा।
- 7- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

- 9- कार्य करने से पूर्व तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर एवं सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग की प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य सुनिश्चित किया जायेगा।
- 10- कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भांति-निरीक्षण उच्चाधिकारियों से अवश्य करा ले निरीक्षण के पश्चात स्थलीय आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।
- 12- धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष-2007-08 की अनुदान सं0-20 के लेखाशीर्षक 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 80-समान्य आयोजनागत, 005-सर्वेक्षण तथा अनुसंधान, 03-निर्माण कार्य, 42-अन्य व्यय के नाम में डाला जायेगा।

2. यह आदेश वित्त विभाग के आशासकीय संख्या-293/XXVII (2)/2007 दि0 20.8.07 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव

संख्या:-2243/11-2007-04(03)/07 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ ।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ।
3. वित्त अनुभाग-2 ।
4. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून ।
5. नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन ।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव